



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गौरवशाली विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

'आस्था स्थलों के संरक्षण से राज्य में पर्यटन का विकास होगा'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थलों के विकास की समीक्षा की

जयपुर, 4 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हमारी प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण अंग हैं। राज्य सरकार इस गौरवशाली विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे आस्था स्थलों का संरक्षण कर हम पर्यटन क्षेत्र को भी विकसित कर सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के साथ

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को राजस्थान की ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करने के लिए स्कूली विद्यार्थियों को प्रसिद्ध स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की नियमित यात्राएं कराई जायेंगी।

विरासत का संरक्षण हमारा ध्येय है और इस पर कार्य करते हुए हम आस्था धामों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को राजस्थान की गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत से रूबरू करवाना ज़रूरी आवश्यक है। इसके लिए स्कूली विद्यार्थियों को प्रसिद्ध स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की नियमित यात्राएं कराई जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में ब्रज चौरासी सर्किट को भक्ति पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। इस हेतु ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग पर पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। शर्मा ने अधिकारियों को जैसलमेर स्थित ननोट माता मन्दिर में विकास कार्य करवाने तथा वहां आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के पास स्थित सांभर लेक क्षेत्र भी गुजरत

के रण क्षेत्र की तरह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। यहां होने वाले सांभर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी सैलानी हिस्सा लेते हैं।

बैठक में राजस्थान घरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सांस्कृतिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव देवस्थान विभाग डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, शासन सचिव पर्यटन रवि जैन सहित, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही, जिला कलक्टर जैसलमेर प्रताप सिंह, जिला कलक्टर भरतपुर डॉ. अमित यादव एवं जिला कलक्टर डीग उत्सव कौशल वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा आर.टी.आई. व्यवस्था को कमजोर कर रही है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 मार्च। कांग्रेस और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा -नीत केन्द्र सरकार पर डेटा प्रोटेक्शन कानून लाकर आर.टी.आई. एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस तानाशाह सरकार से लड़ने को प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा, गुप्त कुक्षु वषों से गलत या झूठी सूचना दिए जाने के क्षेत्र में भारत पहले नम्बर है और मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन लॉ के जरिए कांग्रेस को पूर्व यूपीए सरकार द्वारा लागू गए सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने पर आमादा है।

दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने

पटना, 04 मार्च। बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष पद के लिए आज डॉ. दिलीप जायसवाल के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यहां बापू सभागार में पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉ. जायसवाल की ताजपोशी

■ केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य परिषद की बैठक में यह घोषणा की।

की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी की परंपरा रही है कि तीन साल में संगठन का नए सिरे से गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। खट्टर ने कहा कि बिहार में सांठगतिक रूप से 52 जिलों है, जिनमें से 40 जिलों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के चुनाव प्रभारी राजेश वर्मा के सामने सोमवार को ही डॉ. दिलीप जायसवाल ने नामांकन पत्र भरा था।

■ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उनकी पार्टी आर.टी.आई. एक्ट को कमजोर करने की इस कोशिश के खिलाफ संघर्ष करेगी।

■ कांग्रेस का आरोप है कि केन्द्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की आड़ में राइट टु इन्फॉर्मेशन एक्ट को कमजोर करने पर आमादा है।

उन्होंने कहा कि सूचना चाहे पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हो, जैसे राशन कार्ड की लिस्ट, मनरेगा के लाभान्वित, जनकल्याण कार्यों में शामिल लोगों की लिस्ट, मतदाता, स्कैम करने वाले अरबपति, जो बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर देश से भाग गए हों, यह सब पब्लिक होना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि अभी मोदी

सरकार डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर आरटीआई को कमजोर कर रही है। अब ये नाम सार्वजनिक रूप से नहीं मिलेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है और उनकी पार्टी इसके लिए लड़ती है। पर जब जनकल्याण की बात आती है तो सूचना का अधिकार एक

अनिवार्यता है।

पूर्व कांग्रेस सरकार के अनुभव का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा "कांग्रेस के राज में निजता के अधिकार का भी खयाल रखा गया और सूचना के अधिकार का भी। पर इसका अर्थ यह नहीं कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वितों पर घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए।" कांग्रेस ने कहा कि वह आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी। पार्टी ने पहले भी इसके लिए आवाज उठाई है और आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे।

खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं ने कहा कि हमारी पार्टी इस तानाशाही सरकार से जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी।

अगले वर्ष के विधानसभा....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के मरीन बायोस्फियर रिजर्व में है, जो कोरल रीफ, सी ग्रास का घर है तथा यहाँ काफी दूरी तक फैले मैंग्रोव जंगल हैं, जो तटवर्ती राज्य के लिए उपयोगी हैं। इनसे भोजन, दवाएं व लकड़ी मिलती है, यहाँ कई ऐसे जानवरों व पक्षियों का आवास है, जो दुर्लभ हैं। यह राज्य को तूफानों व ज्वार-भाटे से सुरक्षा देता है। पाक बे में डुगोंग (समुद्री गाय) का संरक्षित आवास है और उस पर इस प्रोजेक्ट का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पाक बे में भारत व श्रीलंका के बीच एक ट्रांस वाउन्डी क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुर्लभ समुद्री जीवों का घर है। यहाँ कई एकड़ क्षेत्र में समुद्री घास फैला है, जो इनका प्रमुख भोजन है।

डुगोंडा को इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) ने "वल्नेबल" श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसके अस्तित्व के लिए भारी खतरा है।

यहाँ खाने करने से लाखों मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है, जो तटवर्ती क्षेत्र के मछुआरों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि गल्प ऑफ मन्नार

के ब्लॉक्स को नीलामों के लिए अधिसूचित करने से पहले राज्य सरकार से विचार-विमर्श नहीं किया गया। स्टालिन ने प्रधानमंत्री से कहा, वे इसमें हस्तक्षेप करें और निर्णय वापस ले लें तथा जैव विविधता वाले क्षेत्र से जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, उनका नाम पैट्रोलियम मंत्रालय में ओपन, एकेरज, लाईसेंसिंग प्रोग्राम (ओ.एल.ए.पी.) से हटाया जाए। यह अधिसूचना 11 फरवरी को जारी हुई थी, जिसमें गल्प ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फियर क्षेत्र का 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, जिसमें 560 वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्री नेशनल पार्क और 448 वर्ग किलोमीटर में फैला डुगोंग रिजर्व भी शामिल है।

केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धर्म में निहित है और यह एक गैर-सांप्रदायिक तकनीक है, जिसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में अनुशासन की एक सख्त संहिता का पालन किया जाता है। पांच मार्च से 15 मार्च तक हमारे वाले 10 दिवसीय ध्यान शिविर में प्रतिभागियों को केन्द्र के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन या समाचार पत्रों का उपयोग करने से बचना चाहिए। कार्यक्रम एक सहायक शिक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा, और प्रतिभागियों को ध्यान के घंटों के बाहर भी पूरी तरह से मौन रहना चाहिए।

नाबालिग से अश्लीलता पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने बताया कि अभियुक्त ने दादी के कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से अदालत को बताया कि उसे प्रकरण में जबरन फंसाया गया है। पुलिस ने घर में काम करने वाली नौकरानी के बयान भी दर्ज नहीं किए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विरोधाभास है। ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुमाने से दंडित किया है।

मद्रास व बॉम्बे हाईकोर्ट में आठ न्यायाधीश नियुक्त

नयी दिल्ली, 04 मार्च। सरकार ने मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में कुल आठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिनमें चार मद्रास उच्च न्यायालय और चार मुंबई उच्च न्यायालय के लिये हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञापन में अनुसार, इनमें मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त चार और मुंबई उच्च न्यायालय

■ मद्रास हाईकोर्ट में 4 अपर न्यायाधीशों को तथा बॉम्बे में 3 को स्थाई किया गया है।

में नियुक्त तीन न्यायाधीश इन न्यायालयों में अपर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्हें उनके वर्तमान न्यायालयों में स्थायी किया गया है।

मुंबई न्यायालय में चौथी नियुक्ति अपर न्यायाधीश के पद के लिए है, जो आगामी आगस्ट से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी। विज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रपति दीपदी मुर्मू ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है। विज्ञापन में अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय में जिन अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है, उनमें न्यायाधीश सर्वामासामी शक्तिवेल, पी. धनवल, चिन्नास्वामी कुमरारण्य और केडासामी राजशेखर का नाम शामिल है।

क्षतिग्रस्त सुरंग में कन्वेयर बेल्ट चालू हुई

नगरकुरनूल, 04 मार्च। तेलंगाना में आंशिक रूप से ध्वस्त सुरंग के अंदर कन्वेयर बेल्ट को ठीक कर लिया गया है और उसने मंगलवार को काम करना शुरू कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि इससे बचाव कार्यों को सुविधा होगी और अंदर फंसे मलबे आदि को निकालने में आसानी और तेजी आएगी।

कन्वेयर बेल्ट 22 फरवरी को हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस बीच दक्षिण मध्य रेलवे की विशेषज्ञ टीम ने सुरंग के अंदर बोरिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म को काट दिया है।

अधिकारी ने बताया कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) परियोजना की ध्वस्त सुरंग के अंदर बचाव अभियान में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर फंसे हुए आठ लोगों को खोजने के प्रयासों में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। बचावकर्मी हर दिन तीन पारियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने और पानी निकालने की प्रक्रिया जारी है।

दरअसल, सुरंग के अंदर भारी मात्रा में कीचड़ और पानी होने के कारण बचाव दलों के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। नगरकुनूल के पुलिस अधीक्षक वैभव गायकवाड़ ने सोमवार को कहा था कि राज्य सरकार बचाव अभियान में बचाव दल को किसी भी खतरे से बचाने के लिए रोबोट तैनात करने पर विचार कर रही है। वैभव गायकवाड़ ने बताया

■ एक अधिकारी के अनुसार, इससे बचाव अभियान में तेजी आएगी।

कि आज सुबह कन्वेयर बेल्ट चालू कर दिया गया है। रेलवे प्लाज्मा मशीनों भी यांत्रिक मलबे को हटाने के लिए काम कर रही है। एसएलबीसी सुरंग परियोजना के इंजीनियर प्रभु श्रीवास्तव का कहना है कि मशीनों द्वारा कटाई का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। खुदाई करने वाली मशीनों अंदर जाएंगी और कन्वेयर बेल्ट पर मलबा बाहर भेजेंगी। रैट माइनर्स, एनडीआरएफ और अन्य टीमें उन जगहों पर काम कर रही हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है। हम नहीं कह सकते कि इसमें और कितने दिन लगेंगे।

हाई कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने गृह जिले या उसके नजदीक के स्थानों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति के लिए आवेदन कर परोक्षा दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक लाने के बावजूद उन्हें गृह जिले में नियुक्ति नहीं दी, जबकि उनसे कम अंक लाने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को गृह जिले या आसपास की स्कूल में नियुक्ति दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत दिसंबर माह में याचिकाकर्ताओं को कहा था कि यह शिक्षा विभाग में इस संबंध में अपना अभ्यावेदन दो। वहाँ, अदालत ने शिक्षा विभाग को कहा था कि वह इन अभ्यावेदनों को तय करे। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने उनके अभ्यावेदनों को तय नहीं किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 19 मार्च तक अभ्यावेदन तय नहीं करने पर शिक्षा निदेशक को हाजिर होकर इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है।

हाईवे के किनारे अवैध...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीटर तक शराब की दुकानों का संचालन अवैध है। इसके बावजूद, प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट व आबकारी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर अवैध तरीके से हाइवे के किनारे ही दुकानें चलाई जा रही हैं।

इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह हाइवे किनारे अवैध तौर पर चल रही शराब की दुकानों को बंद करवाकर उनके लाइसेंस को रद्द करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने करीब एक साल पहले राज्य सरकार और आबकारी विभाग को नोटीस जारी कर जवाब तलब किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

इजरायल ने संघर्ष विराम के लिये नई शर्तें रखीं

यरूशलम, 04 मार्च। इजरायल ने जनवरी में लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए गाजा पट्टी से विदेशीकरण और हमला के शासन की समाप्ति की मांग की है। यह जानकारी इजरायली विदेशी मंत्री गिदोन सांर ने मंगलवार को दी।

गिदोन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारे पास दूसरे चरण पर कोई समझौता नहीं है। हम गाजा से पूरी तरह से विदेशीकरण की मांग करते हैं, और हमारा और इस्लामिक जिहाद को बाहर निकाल कर अपने संबंध को वापसी की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारा इन मांगों पर सहमत हो जाता है तो "हम कल ही समझौते को लागू कर सकते हैं।" रबिवरार सुबह से गाजा में मानवीय सहायता रोकने के इजरायल के कदम का उल्लेख करते हुए, सांर ने दावा किया कि हमारा द्वारा इस सहायता का उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मानवीय आपूर्ति हमारा के लिए बजट की सबसे बड़ी आय बन गई है।

चंडीगढ़ में प्रदर्शन से पहले किसान नेता गिरफ्तार किये गये

मुख्यमंत्री भगवंत मान और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बनेतीजा रहने के बाद कार्यवाही की गई

चंडीगढ़, 04 मार्च। चंडीगढ़ में बुधवार को होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोर्चा नेता बलबीर सिंह राजेवाल को देर रात 1.30 बजे हिरासत में ले लिया गया। कई जिलों में किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की गई और उनको हिरासत में लिया गया है। किसानों ने जगह-जगह पुलिस का विरोध किया। गौरवलब है कि सोमवार को मुख्यमंत्री मान और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बनेतीजा रही थी। तभी सीएस मान बैठक छोड़कर बाहर निकल गए थे, जिसके बाद किसान नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद किसानों ने 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था। पुलिस कार्रवाई पर नेता विपक्ष प्रताप

■ मुख्यमंत्री मान ने कहा कि किसानों की मांगें केन्द्र से हैं, मुद्दा संबंधित नहीं हैं।

सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान पर तंज करते हुए कहा, "महाराजा सतज, अपना होश गवा बैठा, समां हुआ 5 बजे का, दिन-दहाड़े शराब ले बैठा।" विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा - मैं किसानों से पूछा था कि प्रदर्शन का क्या रहेगा? किसानों का कहना था कि जारी रहेगा। फिर मैंने कहा कि मुझे 6 ई घंटे तक क्या बैठाया? ये मांगें मुख्य से संबंधित नहीं थीं। ये मांगें केन्द्र से संबंधित नहीं हैं। इस पर किसानों का

कहना था कि डर कर आप मीटिंग में आए हैं। मैं उन्हें यह कहकर आया था कि मैं मित्र की तरह हूँ। मीटिंग और मोर्चा साथ नहीं चलेगा।

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिड़वां ने कहा कि किसान जब बाहे मीटिंग कर सकते हैं। किसान हमारे संस्कार योग्य हैं। कल मीटिंग काफी अच्छे माहौल में चल रही थी। किसान 18 मांगे लेकर आए थे, 8 मांगों पर सकारं हुई।

चंडीगढ़ पुलिस ने कल होने वाले किसानों के चंडीगढ़ कूच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चंडीगढ़ में एंटी करने वाले 12 पॉइंट्स पर रूट डायवर्ट किए गए हैं और करीब 2500 पुलिसकर्मी और सीनियर अफसर तैनात किए जाएंगे।